नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 062
दि. 04.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव: अब तत्काल टिकट सिर्फ ओटीपी से ही मिलेगा, ब्लैकिंग पर पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने उन लाखों यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव का रास्ता खोल दिया है, जो हर रोज़ तत्काल टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं या सुबह-सुबह ऑनलाइन बुकिंग में सर्वर की धीमी गति से जूझते हैं। रेलवे अब तत्काल टिकट को पूरी तरह ओटीपी आधारित प्रक्रिया से जोड़ने जा रहा है, जिससे टिकटों की पारदर्शिता बढ़ाने, दुरुपयोग रोकने और ब्लैक-मार्केटिंग पर निर्णायक चोट करने की उम्मीद है। इस नई प्रणाली के लागू होते ही किसी दलाल, एजेंट या फर्जी पहचान का खेल लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि टिकट तभी जारी होगा जब यात्री स्वयं अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करेगा। रेलवे इसे अगले कुछ दिनों में देशभर के सभी आरक्षण केंद्रों पर लागू करने जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव पिछले एक वर्ष में टिकटिंग प्रणाली में किए गए कई सुधारों की श्रृंखला का अगला चरण है। जुलाई 2025 में ऑनलाइन तत्काल टिकटों के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू किया गया था, जिसने धोखाधड़ी रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद अक्टूबर 2025 में सामान्य आरक्षण के पहले दिन की बुकिंग को भी ओटीपी वेरिफिकेशन से जोड़ा गया। यात्रियों ने इन दोनों कदमों का स्वागत किया और रेलवे को यह भरोसा मिला कि सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने वाले उपायों के प्रति आम जनता सकारात्मक है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं ने रेल मंत्रालय को तत्काल टिकटों की ऑफलाइन बुकिंग को भी मोबाइल सत्यापन से जोड़ने का साहस दिया। इस बड़े बदलाव की शुरुआत 17 नवंबर 2025 को किए गए उस पायलट प्रोजेक्ट से हुई, जब रेलवे ने देश के कुछ चुनिंदा आरक्षण केंद्रों और 52 ट्रेनों में ओटीपी आधारित

तत्काल टिकट जारी करने की सुविधा शुरू की। शुरुआती रिपोर्टों में यह पाया गया कि ओटीपी प्रणाली लागू होते ही फर्जी आईडी का उपयोग, एक ही व्यक्ति द्वारा कई टिकट उठाने की कोशिश और दलाल तंत्र के माध्यम से ब्लॉक की जा रही बुकिंग में अचानक कमी आ गई। जब वास्तविक यात्रियों से बात की गई तो अधिकांश ने कहा कि ओटीपी की प्रक्रिया भले कुछ सेकंड का अतिरिक्त समय लेती हो, लेकिन इससे उन्हें यह भरोसा मिलता है कि टिकट उनके नाम से सुरक्षित और वैध है तथा कोई तीसरा व्यक्ति इसे ब्लैक में बेच नहीं सकता। सिस्टम के परीक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि आरक्षण काउंटरों पर ओटीपी प्रक्रिया के कारण दो से तीन मिनट का अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद लंबी कतारों में खड़े यात्री यह जानते हुए इंतजार कर रहे थे कि यह इंतजार उन्हें एक असली और सुरक्षित टिकट दिलाने जा रहा है। रेलवे के कर्मचारी भी इस प्रणाली से संतुष्ट नजर आए, क्योंकि टिकट बनाते समय उन्हें अब फर्जी पहचान या संदिग्ध बुकिंग को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत नहीं रहती। सत्यापन का पूरा भार ओटीपी प्रणाली पर आ जाता है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। नई व्यवस्था के लागू होने से दलालों की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अब उनके पास किसी और के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं होगा। पहले वे फर्जी पहचान पत्र, जाली मोबाइल नंबर और कई बार बड़ी संख्या में खरीदे गए सिम कार्ड का उपयोग कर टिकट ब्लॉक कर लेते थे और फिर यात्रियों को ऊंची कीमत पर बेचते थे। लेकिन ओटीपी आधारित सत्यापन यह सुनिश्चित करेगा कि टिकट केवल उसी व्यक्ति के नाम पर जारी हो जो स्वयं मौजूद हो और अपने मोबाइल पर कोड दर्ज करे। इससे न केवल तत्काल टिकटों की ब्लैकिंग में भारी कमी आएगी, बल्कि उन यात्रियों का भरोसा भी लौटेगा जो वर्षों से शिकायत करते रहे थे कि तत्काल कोटा दलालों के कब्जे में है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस परिवर्तन के पीछे मुख्य उद्देश्य यात्रियों को एक ऐसा टिकटिंग माहौल देना है जिसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधा तीनों का संतुलन बना रहे। डिजिटल तकनीक आज देश के लगभग हर क्षेत्र को बदल रही है और रेलवे भी अब तेजी से इसी दिशा में बढ़ रहा है। मंत्रालय का मानना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ भ्रष्टाचार और कदाचार पर रोक लगेगी बल्कि यात्रियों के अनुभव में भी व्यापक सुधार होगा। जल्द ही जब यह प्रणाली देश के सभी आरक्षण केंद्रों और सभी ट्रेनों में लागू होगी, तो भारत का तत्काल टिकट सिस्टम बिल्कुल नए रूप में दिखेगा—सुरक्षित, पारदर्शी और दलालों की पहुंच से पूरी तरह बाहर। यह बदलाव भारतीय रेलवे के उस बड़े और दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर एक और कदम है जहां टिकटिंग पूरी तरह डिजिटल सत्यापन पर आधारित होगी और हर टिकट सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित होगा जिसने वास्तव में यात्रा करनी है।

मोबाइल और ब्रॉडबैंड उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि, डिजिटल कनेक्टिविटी हुई और सशक्त

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सरकार की विभिन्न नीतिगत पहल और सुधारों के परिणामस्वरूप दूरसंचार नेटवर्क का दायरा बढ़ा, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच बढ़ी और डेटा खपत में भी तेज़ी आई। संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में बैंक गारंटी, स्पेक्ट्रम शुल्क और टेलीकॉम लाइसेंस जैसी प्रक्रियाओं को सरल किया, टेलीकॉम टावरों की मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाई और विदेशी निवेशकों के लिए अधिक सुविधा उपलब्ध कराई।

इन सुधारों से ऑप्टिकल फाइबर

नेटवर्क और बेस ट्रांसिवर स्टेशनों का विस्तार हुआ। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम लागू किए गए। मार्च 2018 में देश में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की लंबाई 17.5 लाख किलोमीटर थी, जो अब सितंबर 2025 तक बढ़कर 42.36 लाख किलोमीटर हो गई है। इसी अवधि में बेस ट्रांसिवर स्टेशनों की संख्या 17.3 लाख से बढ़कर 31.4 लाख हो गई। भारत के 6,44,131 गांवों में से 6,34,019 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध है, जिनमें से 6,30,676 गांवों में 4जी सेवा भी उपलब्ध है। ब्रॉडबैंड सदस्यता भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। मार्च 2018 में ब्रॉडबैंड सदस्यता 48 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 98 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री वाणी (PM-WANI) योजना के तहत पूरे देश में 3.80 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं। मोबाइल डेटा खपत में भी लगातार वृद्धि देखी गई है। सितंबर 2018 में प्रति ग्राहक मासिक डेटा खपत 8.32 जीबी थी, जो सितंबर 2025 में बढ़कर 25.24 जीबी हो गई। इस अवधि में डेटा की औसत कीमत प्रति जीबी 10.91 रुपये से घटकर 8.27 रुपये रह गई, जिससे मोबाइल और ब्रॉडबैंड उपयोग और भी सुलभ और किफायती हुआ है। डॉ. चंद्रशेखर ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरकार की पहल और कार्यक्रम देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर रहे हैं और नागरिकों के जीवन में डिजिटल क्रांति ला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार रोजगार, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है।

सोमाली प्रवासियों पर ट्रंप का तीर, अमेरिका में हलचल तेज: कैबिनेट बैठक में दिया विवादित बयान, आव्रजन नीति की नई सख़्ती की आहट

(जीएनएस)। वाशिंगटन। अमेरिकी राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ऐसा बयान दिया, जिसने वाशिंगटन से लेकर मिनेसोटा तक तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है। बैठक के दौरान ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अमेरिका में सोमालियाई प्रवासियों की मौजूदगी नहीं चाहते और उन्होंने उन्हें "कहीं और जाने" की सलाह दी। यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उनकी आव्रजन नीति की दिशा का संकेत भी माना जा रहा है — एक ऐसी दिशा, जहां सख़्ती पहले से कहीं अधिक तेज होती दिख रही है।

करीब दो घंटे चली इस बैठक में माहौल बेहद गंभीर था। व्हाइट हाउस में बैठे कैबिनेट सदस्यों के सामने ट्रंप ने ICE यानी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। जिस तरह ब्रिटेन में कुछ वर्षों पहले प्रवासन को लेकर माहौल अचानक बदल गया था, उसी तरह ट्रंप के ये शब्द भी अमेरिका में एक बड़े राजनीतिक बहस की जमीन तैयार कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया

कि यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब ICE मिनेसोटा में रहने वाले सोमालियाई प्रवासियों को देश से बाहर भेजने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।

युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने बैठक में बताया कि इस अभियान की योजना लगभग पूरी हो चुकी है। यह साफ झलक रहा था कि प्रशासन इस बार किसी प्रतीकात्मक कदम की बजाय व्यापक कार्रवाई की तैयारी में है। प्रशासन के भीतर यह चर्चा तेज है कि पहले चरण में मिनियापोलिस और सेंट पॉल के उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहाँ सोमालियाई समुदाय की आबादी काफी अधिक है। सीएनएन ने एक संघीय अधिकारी के हवाले से बताया कि इन क्षेत्रों में पहचान, पूछताछ, दस्तावेज़ जांच और संभावित निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ट्रंप ने बैठक के अंत में एक बार फिर अपने रुख को और स्पष्ट करते हुए कहा कि वे "उन्हें अमेरिका में नहीं रखना चाहते" और उन्हें अपने देश लौट जाना चाहिए। यह बयान सिर्फ कठोर नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील भी था, क्योंकि मिनेसोटा की प्रतिनिधि इल्हान उमर—जो स्वयं सोमालिया से आईं—पूरे समुदाय की सबसे प्रमुख राजनीतिक आवाज़ हैं। ट्रंप ने बैठक में उनका उल्लेख करते हुए तीखी टिप्पणी की, जिससे कांग्रेस के भीतर भी तीखी बहस छिड़ सकती है।

सोमालिया पहले से ही उन 19 देशों की सूची में शामिल है जिन पर ट्रंप प्रशासन ने यात्रा और आव्रजन संबंधी कड़ी पाबंदियाँ लागू कर रखी हैं। ट्रंप इस देश को कई बार "अस्थिर, अव्यवस्थित और असुरक्षित" कह चुके हैं, और बार-बार यह सवाल उठा चुके हैं कि क्यों ऐसे देशों से आने वाले लोग अमेरिकी भूमि पर बसाए जाएँ। उनके इस बयान के बाद साफ है कि व्हाइट हाउस की सोच अब किसी भी नरमी की दिशा में नहीं जा रही। बल्कि यह भी संकेत मिल रहे हैं कि प्रशासन आव्रजन प्रणाली को एक ऐसे ढर्रे पर ले जाना चाहता है, जहाँ 'शून्य सहनशीलता' जैसी नीतियाँ फिर लौट सकती हैं।

मिनेसोटा का सोमाली समुदाय दशकों से मेहनतकश, नौकरीपेशा और छोटे कारोबारों से जुड़ा रहा है। लेकिन अब उनके सामने भय और अनिश्चितता का साया फिर मंडराने लगा है। समुदाय के धार्मिक नेताओं, सामाजिक संस्थाओं और नागरिक अधिकार समूहों के प्रतिनिधि इस बयान को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यह बयान केवल एक टिप्पणी नहीं — बल्कि आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन का संकेत है।

अमेरिका में 2025 की राजनीतिक हवा पहले ही ध्रुवीकृत है, और ट्रंप के इस बयान ने इसे और तेज कर दिया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स दरों को बनाए रखने का प्रावधान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025' पेश किया। यह विधेयक सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है और इसे लोकसभा में चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा गया है।

विधेयक के अनुसार, भारत में निर्मित या आयातित सामान पर लगाए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर वर्तमान कर स्तर को बनाए रखना और राजस्व के स्थायित्व को सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से यह विधेयक बिना तैयार तंबाकू, तैयार तंबाकू, तंबाकू उत्पाद और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने की प्रावधान करता है। इससे सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तंबाकू उत्पादों पर वर्तमान टैक्स स्तर कम न हो और इसके राजस्व में कोई गिरावट न आए।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन से तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर नियंत्रण अधिक सख्त होगा। विधेयक का उद्देश्य केवल कर संरचना को बनाए रखना नहीं है, बल्कि तंबाकू के विकल्पों और नई श्रेणियों पर भी कराधान की स्पष्ट रूपरेखा स्थापित करना है। इससे उद्योग को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और सरकार को स्थिर राजस्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सरकार के व्यापक वित्तीय रणनीति का हिस्सा है, जिससे उत्पाद शुल्क के जरिए स्वास्थ्य और सामाजिक पहलुओं के साथ राजस्व संग्रह में संतुलन बनाए रखा जा सके। विधेयक सोमवार को संसद में पेश किया गया था और वर्तमान में लोकसभा में इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। चर्चा के दौरान विधायिका सदस्यों ने तंबाकू उद्योग, स्वास्थ्य पहल, और कर संग्रह के प्रभावों पर विचार व्यक्त किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह संशोधन भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर कर दरों का संतुलन बना रहे, जिससे सरकार के राजस्व संग्रह में स्थायित्व आए और स्वास्थ्य नीतियों के अनुरूप उत्पाद शुल्क व्यवस्था को लागू किया जा सके। लोकसभा में इस विधेयक पर आगे की चर्चा और मतदान की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में संपन्न होने की संभावना है। इसके पारित होने के बाद तंबाकू उत्पादकों और संबंधित व्यापारिक संगठनों को नए कर ढांचे के अनुसार अपनी उत्पादन और विपणन रणनीतियों में संशोधन करना होगा।

देशभर के हवाई अड्डों पर तकनीकी संकट से उड़ी यात्रियों की नींद, घंटों ठप रहा चेक-इन सिस्टम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बुधवार सुबह भारत के लगभग हर प्रमुख हवाई अड्डे पर यात्रियों के सामने एक ऐसा दृश्य था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हजारों लोग कतारों में खड़े थे, गेटों पर अफरा-तफरी थी, घोषणाएं बार-बार बदली जा रही थीं और एयरलाइन कर्मचारी परेशान यात्रियों को समझाने में लगे थे। वजह थी—एक ऐसी तकनीकी गड़बड़ी जिसने देशभर के एयरपोर्ट्स पर चेक-इन व्यवस्था पूरी तरह से थाम दी। सुबह लगभग आठ बजे यह समस्या अचानक पैदा हुई और देखते ही देखते इसका असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई सहित लगभग सभी बड़े हवाई अड्डों पर दिखाई देने लगा। एयरलाइंस जो सामान्य दिनों में मिनटों में हजारों यात्रियों का चेक-इन कर लेती हैं, वे कंप्यूटर सिस्टम के बंद हो जाने के बाद बेहद असहाय नजर आईं। यह बताया गया कि जिस आईटी सिस्टम पर एयरपोर्ट और एयरलाइनें निर्भर हैं, वह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वैश्विक सेवाओं में आई एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी के बाद अचानक क्रैश हो गया।

चूंकि एयरपोर्ट के चेक-इन काउंटरों पर एक ही तरह के सॉफ़्टवेयर का उपयोग होता है, इसलिए विफलता का असर तुरंत हर टर्मिनल पर फैल गया। इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस—चारों एयरलाइंस के काउंटर ठप पड़ गए। कर्मचारी पहले समस्या की वास्तविक वजह खोजते रहे, फिर जब स्पष्ट हुआ कि सिस्टम तुरंत ठीक नहीं होने वाला, तब उन्हें तुरंत पुराने तरीके का 'मैन्युअल चेक-इन' शुरू करना पड़ा। इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है, इसलिए कुछ ही मिनटों में कतारें लंबी होती चली गईं। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे चेक-इन के लिए दो-दो घंटे से खड़े हैं, जबकि उनकी उड़ान का समय निकलने वाला है।

हवाई अड्डों के अंदर का माहौल धीरे-धीरे तनावपूर्ण होता गया। कुछ यात्री अपनी उड़ानें छूट जाने के डर से बहस पर उतर आए, कुछ ने शिकायत की कि उन्हें समय पर कोई सूचना नहीं दी गई। एयरलाइंस के कर्मचारियों ने बार-बार यात्रियों को आश्वस्त करने की कोशिश की कि समस्या अस्थायी है और टीमें लगातार सिस्टम को रीस्टोर करने में लगी हैं। कई यात्रियों ने यह भी कहा कि वे पहली बार देख रहे हैं कि डिजिटल व्यवस्था के भरोसे खड़ा पूरा ढांचा कुछ ही सेकंड में ठप पड़ सकता है।

दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) की टीमें, तकनीकी विशेषज्ञ और एयरलाइंस के आईटी विभाग सभी मिलकर लगातार कोशिश में जुटे रहे कि सिस्टम को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में लाया जाए। लेकिन शुरुआती तीन घंटे तक किसी भी स्तर पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। एयरलाइंस को मजबूर होकर कई उड़ानों का बोर्डिंग समय बदलना पड़ा और कुछ उड़ानों को रनवे पर खड़ा रखकर इंतजार करना पड़ा। इसके कारण विमान संचालन का पूरा चक्र प्रभावित हुआ और देरी का असर अगले कई घंटों तक उड़ानों पर दिखता रहा।

यद्यपि यह गड़बड़ी वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट की सेवा ठप होने से जुड़ी बताई गई है, लेकिन अभी तक कंपनी या प्रभावित एयरलाइंस की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आईटी संरचनाएं जब एक ही सिस्टम पर आधारित हों, तो इस तरह की तकनीकी विफलता का प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है और हवाईअड्डे, बैंक तथा अस्पताल जैसे जरूरी ढांचों पर ऐसी घटनाएं गंभीर असर डाल सकती हैं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

देर से सही, सीबीआई जांच स्वागत योग्य

यह विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक ठगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजाय शीर्ष अदालत की पहल पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करे, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर की सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन-देन की गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार म्यांमार,कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निस्संदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें।

दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों-टुकड़ों में जांच सीमा-पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है। दरअसल, साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिये भोले-भाले लोगों व बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। वे कानून प्रवर्तन अधिकारी या जज बनकर मोटी रकम देने के लिये उन्हें आतंकित करते हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति से एक करोड़ रुपये की ठगी के बाद अदालत ने इस व्यापक समस्या का स्वतः संज्ञान लिया। उन्हें धमकाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेशों का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति है कि साइबर अपराधी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल रहे हैं। तभी शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, देश की केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की तह तक तुरंत पहुंचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग को भी सिम कार्ड के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये कहा गया है। निश्चित रूप से कोर्ट की सार्थक पहल के बाद यदि ये सभी उपाय सिरे चढ़ते हैं तो इस गंभीर अपराध के खिलाफ एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा। कोर्ट ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय एजेंसी बिना किसी भय या पक्षपात के जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। इसमें राज्य सरकारों की सक्रियता व सजगता भी सीबीआई को अपराध की तह तक पहुंचने में मददगार सबित हो सकती है। यह भी जरूरी है कि एजेंसी की कार्रवाई में लालफीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। इसके साथ ही नागरिकों को भी ऐसे अपराधों के प्रति सजग रहना होगा। जागरूकता-सतर्कता उन्हें अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचा सकती है। ऐसी किसी कॉल के आने पर उन्हें रुककर विचार करना चाहिए और हड़बड़ी में बैंक से जुड़ी कोई जानकारी देने से बचना चाहिए।

राह दिखाती सांप्रदायिक सौहार्द की एक उजली

> “ हम किस धर्म में विश्वास करने वाले परिवार में जन्म लेते हैं इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है, यह एक संयोग मात्र है। लेकिन इस संयोग को सार्थक बनाने का दायित्व हमारा है। एक अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, या अच्छा ईसाई बनना अवश्य हमारे हाथ में है। यह अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने अच्छे मनुष्य हैं।

उसका नाम अरफाज अहमद डैंग है। शायद ही सुना होगा आपने यह नाम। उसने ऐसा कोई कारनामा भी नहीं किया है कि यह नाम सुर्खियों में आता। असल में अरफाज जम्मू का एक युवा पत्रकार है, जिसकी एक पहचान यह भी है कि वह अपने निजी चैनल से बड़ी हिम्मत के साथ सच्चाई को उजागर करने का दावा करने वाला पत्रकार है। कुछ दिन पहले उसने एक समाचार प्रसारित किया था, जो कुछ ताकतवरों को नागवार गुजरा और 'उसे सबक सिखाने के लिए' उसका चालीस साल पुराना मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह मकान अनधिकृत निर्माण था, इसलिए उचित नोटिस देकर इसे गिरा दिया गया। चालीस साल से अपने माता-पिता के साथ वहां रहने वाले अरफाज ने इस कार्रवाई को गैर-कानूनी और तानाशाही गतिविधि करार दिया है।

इस घटना की हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आयेगी, पर यह एक सच्चाई तो है ही कि पिछले एक लंबे अर्से से देश में 'बुलडोजरी न्याय' की प्रक्रिया जारी है। इस आशय के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं जो इस प्रक्रिया को एक सीमा तक अनुचित ठहराते हैं। यहां मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वह 'अनधिकृत निर्माण' और 'बुलडोजरी न्याय' से कुछ अलग है। मुद्दा यह है कि अरफाज के एक पड़ोसी ने अरफाज के सिर को छत से वंचित करने की इस कार्रवाई को 'अत्याचार' कहा है। पर बात यहीं नहीं रुकती। इसके आगे जो हुआ वह बहुत कुछ कह रहा है और इसे 'सुना' जाना चाहिए।

इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है वह एक मुसलमान के हिंदू पड़ोसी की मानवतावादी सोच को उजागर करता है। इस हिंदू पड़ोसी का नाम है कुलदीप शर्मा। अरफाज के पिता की उम्र के इस हिंदू पड़ोसी ने दोनों परिवारों के चालीस साल साथ रहने की दुहाई देते हुए कहा है कि वे अरफाज और उसके परिवार को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। बुलडोजर ने अरफाज का तीन महले का घर तोड़ा है, कुलदीप शर्मा ने अरफाज के परिवार को पांच मरला ज़मीन उपहार में देकर उस पर मकान बनवाने का आश्वासन भी दिया है। घटना के वायरल हुए वीडियो में कुलदीप शर्मा को आंसू बहाते हुए यह कहते दिखाया गया है कि वे 'भीख मांगकर भी' अपने पड़ोसी मुस्लिम परिवार को नया मकान दिलाएंगे।

Advertisement

हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का यह शानदार उदाहरण ज़रूर है, पर अकेला उदाहरण नहीं है। ऐसे ढेरों उदाहरण देखे जा चुके हैं जो हमारे देश की गंगा-यमुनी सभ्यता को उजागर करते हैं। अक्सर ऐसे उदाहरणों को नज़रंदाज कर दिया जाता है, पर इन्हें याद रखा जाना ज़रूरी है। जिस तरह का आपसी वैमनस्य फैलाने वाला माहौल देश में पनप रहा है, उसमें अरफाज और कुलदीप शर्मा से जुड़ी यह घटना भरोसा देने वाली है। शर्मा जी ने जो जमीन अपने मुसलमान पड़ोसी को उपहार में दी है, उसके कागज़ात उन्होंने अपनी किशोरी पुत्री के हाथों 'अपने अरफाज भाई' को दिलवाये हैं। इस अवसर पर पुत्री का यह कहना कि मैं 'खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसे मां-बाप मिले हैं' किसी भी सच्चे भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा उठा देगा।

देश के नागरिकों में आपसी सौहार्द की दिखती यह उजली किरण अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए या फिर धर्म के नाम पर भारतीयों को बांटने की नीति में विश्वास के कारण आज देश में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, जिसे देखकर हर विवेकशील भारतीय को चिंतित होना चाहिए। हमारी राजनीति के कर्णधार कभी 'अस्सी और बीस' की बात करते हैं, कभी मंदिर-मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, कभी विधर्मियों के सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार का नारा लगाते हैं। यह प्रवृत्ति समाज और देश को बांटने वाली है, जोड़ने वाली नहीं।

विभिन्नता में एकता का आदर्श उदाहरण है हमारा देश। हमारी धार्मिक विभिन्नता हमारी कमज़ोरी नहीं, ताकत है। इस बात के मर्म को पहचानना-समझना ज़रूरी है। और यह मानना भी ज़रूरी है कि हमारा भारत अस्सी करोड़ हिंदुओं, बीस करोड़ मुसलमानों और चालीस करोड़ अन्य धर्मों को मानने वालों का देश नहीं, एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों का देश है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि दुनिया के सारे धर्मों के लिए हमारे देश में जगह है; हम वसुधैव कुटुंबकम् में विश्वास करते हैं और सर्वे भवंतु सुखिनः हमारा जीवन-मंत्र है। यह सब हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया था, फिर यह कैसे हुआ कि आपसी भाईचारे के इस महामंत्र को हम भूल रहे हैं?

धर्म के नाम पर बंटने-बांटने की बात करने वाले हिंदू या मुसलमान या ईसाई होने पर गर्व करें, इसमें कुछ ग़लत नहीं है। ग़लत यह तब हो जाता है जब हम अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरों की लकीर को छोटा करने लगते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम किस धर्म में विश्वास करने वाले परिवार में जन्म लेते हैं इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है, यह एक संयोग मात्र है। लेकिन इस संयोग को सार्थक बनाने का दायित्व हमारा है। एक अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, या अच्छा ईसाई बनना अवश्य हमारे हाथ में है। यह अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने अच्छे मनुष्य हैं।

इसी अच्छाई का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जम्मू-कश्मीर के कुलदीप शर्मा ने प्रस्तुत किया है। अपने मुसलमान पड़ोसी अरफाज अहमद के ध्वस्त किये गये मकान को फिर से बनवाने के लिए अपनी ज़मीन उपहार में देकर कुलदीप शर्मा ने एक अच्छे हिंदू होने का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। अच्छा हिंदू सबकी भलाई में विश्वास करता है, सबको अपना परिवार मानता है–विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही तो सिखाया जाता है हमें अपनी प्रार्थनाओं में। फिर कोई कुलदीप किसी अरफाज को पराया कैसे समझ सकता है?

इस संकीर्णता से उबरना होगा हमें। हम तो और संकीर्ण होते जा रहे हैं। कुछ ही अर्सा पहले महात्मा गांधी के प्रिय भजन 'रघुपति राघव राजा राम' को लेकर विवाद खड़ा करने की हास्यास्पद कोशिश हुई थी। कहा गया कि इस भजन में ईश्वर-अल्लाह तेरा नाम वाली पंक्ति मूल भजन में नहीं थी, गांधीजी ने इसे जोड़ा। निवेदन है कि यदि यह पंक्ति नहीं भी थी तो उसमें ग़लत क्या है? क्या ईश्वर, गॉड या अल्लाह या परमात्मा एक ही शक्ति के नाम नहीं हैं? कोई भी नाम देकर ईश्वर को पुकारा जा सकता है– सवाल सिर्फ यह है कि हमारी पुकार में कितनी ईमानदारी है! बहरहाल, अरफाज अहमद ने अपने डिजिटल चैनल पर किसी ड्रग रैकेट का खुलासा किया था, इसी बात की उसे सजा दी गयी, ऐसा कहा जा रहा है। पर यह पूरा प्रकरण हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में वायरल हुए वीडियो में कुलदीप यह कहते सुनाई देते हैं कि हिंदू-मुस्लिम भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। सच है, ऐसे उदाहरण इस भाईचारे को कभी खत्म नहीं होने देंगे। यह हमारा दायित्व बनता है कि हम वह सब करें जो इस भाई-चारे को बनाये रख सकता है।

प्रेरणा

मंच पर कविता का महाभारत और मिसिरबाबू की ऐतिहासिक बचाव कथा

मिसिरबाबू, आपको लाख-लाख बधाइयाँ, बल्कि कहूँ तो इस बार तो आपको साहित्यिक इतिहास में एक विशेष अध्याय दिया जाना चाहिए—"मंचीय कविताओं के महाभारत से जीवित वापस लौटने वाले कुछ बचे हुए मनुष्यों की सूची" में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जिस संग्राम से आप बच निकले हैं, उसे साधारण लोग कवि-सम्मेलन कहते हैं, मगर जो भीतर का हाल जानते हैं, वे समझते हैं कि वह असल में युद्धभूमि है, और वह भी बिना हथियारों वाला युद्ध नहीं—यहाँ माइक मिसाइल बन जाता है, हूटिंग बम बन जाती है और तालियों के ठहाके रसायनिक हथियारों की तरह काम करते हैं।

कभी सोचिए मिसिरबाबू, कविता वह साधना थी जो रात के तीसरे पहर में लिखी जाती थी। कवि वह प्राणी था जो आधी दुनिया के सो जाने पर जागता था, शब्दों की चादर बुनता था, और अपने मन के अंधेरों में दीपक जलाता था। लेकिन आज का कवि मंच पर चढ़ते ही ऐसा व्यवहार करता है जैसे प्राचीन काल से इसी पल की प्रतीक्षा में खड़ा था। वह कविता कम और नारा ज्यादा पढ़ता है। कविता का वजन उसकी पंक्तियों में नहीं, उसकी आवाज़ की ऊँचाई और तालियों की गूँज में मापा जाने लगा है। और श्रोता? वे अब पंक्तियों का मर्म नहीं, पंचलाइन का तीखा स्वाद ढूँढते हैं। जैसे कविता नहीं, चाट का स्टॉल लगा हो—तेज़, मसालेदार, और जितनी जल्दी खाई जाए उतना अच्छा।

समाज का हाल भी अजब है मिसिरबाबू। मोहल्ले के शर्मा जी, जिनकी अलमारी में कभी 'दिनकर', 'निराला', 'त्रिलोचन' और 'बच्चन' की किताबें एक सैनिक की तरह खड़ी रहती थीं, आज वही शर्मा जी पाँच सौ रुपये का टिकट लेकर कवि-सम्मेलन में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ 'हँसी' सस्ती पड़ती है और 'ज्ञान' बहुत महँगा। उन्हें कविता में रस नहीं चाहिए, उन्हें ठहाकों का बोनस चाहिए, क्योंकि अब कविता नहीं, 'मनोरंजन' बिकता है, और मनोरंजन की कीमत तालियों से तय होती है।

कवि-सम्मेलनों की इस अजीबोगरीब क्रांति की गूँज पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, यह यमलोक तक पहुँच चुकी है। वहाँ चित्रगुप्त बेचारे इतने परेशान हैं कि उनका 'कविता-लेजर सॉफ़्टवेयर' रोज़ क्रैश हो जाता है। यमराज ने एक दिन गुस्से में मीटिंग बुला ली और बोले—"चित्रगुप्त! क्या हो रहा है यह? कल तक कविता लिखने वाले पुण्य कमाते थे, आज हर दूसरे कवि के खाते में 'मंच पर उखाड़ा गया', 'तालियाँ कम मिलीं', 'हूटींग से स्थिति बिगड़ी' जैसी एंट्रियाँ क्यों आ रही हैं?" चित्रगुप्त ने सिर पकड़ लिया और बोला—"प्रभु, अब पुण्य-पाप कविता से नहीं, तालियों की मात्रा से तय होता है। जिसने तालियों का सागर पाया वह पुण्यवान। जिसे मंच पर बेइज्जती मिली, सीधा नर्क का टिकट।" यमराज ने अफसोस किया कि अगर ऐसा चलता रहा, तो शांति से कविता लिखने वाले कवि सीधे स्वर्ग से बेदखल हो जाएँगे क्योंकि उन्होंने मंच पर खुद को नहीं बेचा। युद्ध का यह नया रूप मनुष्य को घायल नहीं करता, उसकी प्रतिष्ठा को घायल करता है। यहाँ, मिसिरबाबू, खून नहीं बहता—सम्मान बहता है। तलवारें नहीं चलतीं—टिप्पणियाँ चलती हैं। तीर नहीं छोड़े जाते—"फ्लॉप कवि" और "कॉपी-पेस्ट कवि" के तंज़ छोड़े जाते हैं। यह वह युद्धभूमि है जहाँ हर कवि किसी दूसरे कवि का प्रतिद्वंद्वी है, चाहे दोनों की कविता दो अलग दिशाओं में जाती हो। संयोजक कवि को ब्लॉक कर देता है, कवि संयोजक को अनफ्रेंड कर देता है, और जो मंच पर एक बार ज्यादा तालियाँ झटक ले गया, वह रातों-रात "महाकवि" बन जाता है। कविता की गुणवत्ता का अब कोई मापदंड नहीं—बस तालियों की संख्या ही अंतिम सत्य है।

और उस पर भी, इस युद्ध की असली सेना तो वे लोग हैं जो मंच के नीचे बैठकर मोबाइल में वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल बनकर साहित्य जगत का भविष्य तय करते हैं। ये सेना किसी विचारधारा के पैरोकार नहीं—ये सिर्फ ट्रेंड के पुजारी हैं। इन्हें कविता का अर्थ नहीं चाहिए—इन्हें मीम चाहिए। इन्हें भावनाओं की गहराई नहीं चाहिए—इन्हें वायरल होने वाला एक चुटकुला चाहिए।

लेकिन मिसिरबाबू, इस सब के बीच आप अब तक शांत, स्वस्थ और बिना किसी स्टेजीय आघात के कैसे बच गए? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यह युद्ध किसी को छोड़ता नहीं। आज आप बच गए हैं, पर कल को कौन जानता है कि कहीं कोई नया सरकारी आदेश न आ जाए—"एक देश, एक कवि-सम्मेलन"! हो सकता है कि आने वाले समय में राशन कार्ड, वोटर आईडी, गैस कनेक्शन सब कुछ आपके 'मंचीय प्रदर्शन' से जुड़ जाए। हो सकता है कि नागरिकता साबित करने के लिए कविता सुनानी पड़े। हो सकता है कि डीजे वाले भी कह दें—"पहले कविता पढ़ो, फिर गाना बजाएँगे।"

तब क्या होगा मिसिरबाबू? तब आपकी वह शांत, आत्ममुग्ध, बिना तालियों वाली छोटी-सी कविता डायरी भी अदालत में पेश करनी पड़ेगी और बताया जाएगा—"ये हैं मिसिरबाबू, इन्होंने कभी मंच पर शोर नहीं मचाया, इसलिए संदेह है कि ये कवि ही नहीं थे।" और फिर कोई अधिकारी आपकी आँखों में झाँककर पूछेगा—"आपने आख़िरी बार किस मंच पर कविता पढ़ी थी?" और आप अपनी सादगी से कहेंगे—"मैं तो कविता अपने लिए लिखता हूँ।" तब वे आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने देशद्रोह स्वीकार कर लिया हो। लेकिन तब तक, जब तक समय की यह आँधी आपको छूकर भी न गयी है, जब तक आप मंचीय राजनैतिकरण की इस किताब के पन्ने में नहीं फँसे, जब तक आपकी कविता का अस्तित्व तालियों पर निर्भर नहीं बना—उतनी देर के लिए आपको दिल से बधाई। क्योंकि आपने कविता को कविता ही रहने दिया, उसे तमाशा नहीं बनाया। और यह भी याद रखिए मिसिरबाबू, कवि-सम्मेलनों के इस महाभारत में हर दिन नई लाशें दफन होती हैं—कविता की, कवि की, और कभी-कभी साहित्य की भी।

अदूरदर्शी नीतियों से उपजा प्रदूषण संकट

वर्तमान में दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3.46 करोड़ और जनसंख्या घनत्व लगभग 27,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आजादी के बाद, अदूरदर्शी सरकारी तंत्र ने दिल्ली को औद्योगिक नगरी बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई। वर्ष 1901 में दिल्ली की जनसंख्या 4 लाख थी, जो 1947 में केवल 7 लाख हुई, लेकिन अगले 4 वर्षों में ही दुगनी से अधिक होकर 17 लाख हो गई। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली की कुल जनसंख्या 17,44,072 में से 10,26,762 लोग दिल्ली के बाहर पैदा हुए थे। सरकार ने शरणार्थियों को बसाने और उनके पुनर्वास व रोजगार आदि देने के लिए मुफ्त और रियायती दरों पर मकान, दुकान, उद्योग, बिजली, सस्ते ऋण आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की। उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र को दी गई भारी रियायतों और बेहतर रोजगार सुविधाओं की बदौलत, आजादी के बाद दिल्ली में प्रवासी जनसंख्या प्रत्येक दशक में लगभग दुगनी होती गई। अगस्त, 2025 में लगभग 73 लाख यानी 21 प्रतिशत दिल्लीवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में मुफ्त राशन ले रहे हैं, जो राजधानी की गरीबी की पोल खोल रहे हैं। कई हजार अवैध गंदी बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियों का जमावड़ा, भीड़-भाड़ वाली टूटी-फूटी धूल से भरी सड़कें, प्रदूषित वायु और यमुना का प्रदूषित पानी, अब दिल्ली की पहचान बन गए हैं। दिल्ली में 1950 तक, केवल 8 हजार छोटे-बड़े उद्योग थे, जो 2021-22 में बढ़कर 8.75 लाख और वर्ष 2025 में एक मिलियन से ज्यादा हो गए। इनमें 40 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत हैं, जो दिल्ली में कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग 30 प्रतिशत हैं। फरवरी, 2025 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 39 लाख पेट्रोल-डीजल चलित और 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3.3 करोड़ पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहन हैं। दिल्ली के दोषपूर्ण शहरीकरण नियोजन मॉडल को अपनाकर पड़ोसी राज्यों ने भी 90 किलोमीटर घेरे में 50 से ज्यादा औद्योगिक नगर बसाकर, दिल्ली में प्रदूषण को कई गुणा बढ़ाया है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा 31 दिसंबर, 2024 को दिए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का वार्षिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक कोविड वर्ष 2020 को छोड़कर कई दशकों से खराब श्रेणी में रहा है। जहां मानसून वर्षा के 3 महीनों (जुलाई-सितंबर) को छोड़कर पूरे वर्ष एक्यूआई 200 से ज्यादा रहता है, और अक्तूबर महीने में मानसून वापसी पर वायु गति कम होने से एक्यूआई 300 के पार चला जाता है, और सर्दी के 4 महीनों नवम्बर-फरवरी में हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं से तापमान गिरने के कारण, प्रदूषण के कणों का घनत्व वायुमंडलीय निचली सतह पर बढ़ जाने से वायु प्रदूषण बहुत गंभीर होकर जीवों की जान को खतरा बन जाता है।

आईपीसीसी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में कुल वायु प्रदूषण में अकेले वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान लगभग 72 प्रतिशत है, जबकि उद्योग, सड़कों और निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जन होने वाला धुआं-धूल और दूषित जल आदि दूसरे मुख्य कारक हैं।

वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत, कई दशकों से सरकारी तंत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए किसान और धान पराली को खलनायक के रूप में प्रचारित करके, वायु प्रदूषण के असली गुनहगार वाहन-उद्योग को बचा रहा है। भारत सरकार के वायु गुणवत्ता जांच केंद्र के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 में 26 नवम्बर तक (330 दिन), दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली का योगदान लगभग नगण्य रहा, जो सिर्फ 4 दिन 10 प्रतिशत से अधिक रहा है। सरकार करोड़ों रुपये वार्षिक व्यय करके, अव्यावहारिक एक्स सीटू विधि (खेत से पराली के बंडल बनाकर उद्योग में उपयोग), बायोडीकंपोजर छिड़काव से पराली प्रबंधन आदि से किसानों को भ्रमित कर रही है। 6 नवंबर, 2025 को, हरियाणा के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि प्रदेश में 40 लाख एकड़ धान फसल से उत्पादित कुल 12 मिलियन टन पराली में से मात्र 1.9 मिलियन टन (लगभग 16 प्रतिशत) का प्रबंधन एक्स सीटू विधि से हुआ है। जबकि बाकी 84 प्रतिशत धान पराली का प्रबंधन किसानों ने इन-सीटू विधि (पराली को खेत में दबाकर जैविक खाद बनाना) आदि से किया। इसलिए सरकार को पर्यावरण हितैषी इन-सीटू समाधान के लिए किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ ही, वर्ष 2018 के आदेश 'कम्बाइन हार्वेस्टर पर एसएमएस अनिवार्य' करने को सख्ती से लागू करना चाहिए। वायु प्रदूषण के मुख्य कारकों में वाहन-उद्योगों से उत्सर्जन के खिलाफ सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सरकार अव्यावहारिक कृत्रिम बारिश, सड़कों पर पानी छिड़काव जैसे प्रचार से जनता को भ्रमित कर रही है। एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे। इस निर्णय ने भारत में पर्यावरण कानून में 'पूर्ण दायित्व सिद्धांत' और 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' को स्थापित किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सरकारी तंत्र ने वोट राजनीति के चलते प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया। आज वायु प्रदूषण फैलाने और यमुना जल को प्रदूषित करने वाले उद्योग और पेट्रोल-डीजल चलित करोड़ों वाहन लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं।

अभियान

अनंत ज्योति-स्तंभ की अद्भुत लीला और शिवलिंग की उत्पत्ति का कालातीत रहस्य

सृष्टि के उस अमूर्त काल में, जब न दिन था न रात, न दिशा थी न गमन, सब कुछ एक अव्यक्त चेतना की हल्की-सी तरंगों के रूप में तैर रहा था। ब्रह्मांड एक अदृश्य गर्भ की तरह अपनी ही मौन धड़कनों से आकार ले रहा था। तारों की धूल भी तब तक तारों में नहीं बदली थी, समय अभी तक अपने पंख खोलकर उड़ना नहीं सीखा था, और संसार के तीनों महाशक्तियों के स्वरूप धीरे-धीरे अपनी-अपनी भूमिकाएँ ग्रहण कर रहे थे। उसी काल में एक घटना घटी, जिसने न केवल देवताओं की चेतना को झकझोर दिया, बल्कि ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा चिह्न स्थापित कर दिया जिसे आज हम शिवलिंग कहते हैं।

ब्रह्मा और विष्णु — दो दिव्य शक्तियाँ, दो विशाल महातत्त्व। एक सृष्टि को रचने वाला, दूसरा सृष्टि को संवारने और संतुलित रखने वाला। दोनों अपने-अपने कार्यों में अद्वितीय, अद्भुत और आदरणीय। पर एक दिन भीतर कहीं एक अदृश्य तरंग उठी जिसने दोनों के मन में श्रेष्ठता की भावना को जगाया। ब्रह्मा ने कहा — "मैं सृष्टि का जनक हूँ, इसलिए सर्वोच्च मैं हूँ।" विष्णु ने कहा — "मेरे बिना कोई सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए सर्वोच्च मैं हूँ।" इस विवाद की अग्नि धीरे-धीरे देवलोक तक पहुँची। देव, गंधर्व, अप्सराएँ, सिद्ध, महर्षि — सभी चकित थे कि क्या वास्तव में इतनी महान शक्तियाँ भी इस

प्रकार की तुलना में उलझ सकती हैं?

अंततः निर्णय हुआ कि इस विवाद का समाधान केवल वही दे सकता है जो त्रिगुणों, काल, शरीर, जन्म, मृत्यु और कारण-कार्य के संबंधों से परे है। वही जो न रचना में बंधा है, न पालन में, न संहार में। वही जो अनादि, अनंत, निराकार और सर्वोच्च सत्ता है — महादेव शिव।

सब देवता संग-साथ ब्रह्मा और विष्णु शिवलोक की ओर चले। कैलाश का शांत, श्वेत, दिव्य स्वरूप उनकी यात्रा को अलौकिक बना रहा था। पर्वत की चोटियाँ मानो स्वयं शिव के आध्यात्मिक आभामंडल में डूबी हुई थीं। जब वे कैलाश पहुँचे, तब महादेव गहन समाधि में थे। परंतु शिव और समाधि एक ही तत्व हैं — वे सब जानने वाले, सब देखने वाले, सब होने वाले। उन्होंने देवताओं की उपस्थिति का संज्ञान लिया, समाधि से बाहर आए और अपनी आधे-खुले नेत्रों से ऐसा प्रकाश फैलाया कि देवलोक भी उस प्रकाश में तिरोहित हो गया।

ब्रह्मा और विष्णु ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि वे उनके बीच के विवाद को दूर करें। शिव मुस्कुराए — वह मुस्कान न करुणा की थी, न उपेक्षा की, बल्कि परम शांति और अनंत ज्ञान की थी।

शिव बोले — "जिसे लगता है कि वह सर्वोच्च है, वह मेरी अग्नि-ज्योति का अंतिम छोर ढूँढकर दिखाए। जो मेरी ज्योति की सीमा पा लेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा।" जैसे ही शिव ने यह कहा, एक प्रचंड प्रकाश-स्तंभ, अग्नि की अनंत धारा, उनके भीतर से उत्पन्न हुई। वह न ऊपर खत्म होती थी, न नीचे, न दाएं, न बाएं — वह सब दिशाओं में अनंत तक जाती थी। वह प्रकाश साधारण प्रकाश नहीं था — वह सृष्टि का आदितेज था, काल का मूल कंपन था, ऊर्जा का परम विराट स्वरूप था। उसका तेज इतना दीप्त था कि देवताओं की चेतना काँप उठी, परंतु वह प्रकाश किसी को न जला सकता था, न नष्ट कर सकता था — क्योंकि वह शिव का स्वरूप था, विनाशक नहीं, चेतना का शुद्ध स्तंभ।

विष्णु बोल उठे — "मैं निचला छोर ढूँढूँगा।" और तुरंत ही वे विशाल वराह रूप में परिवर्तित होकर पाताल की ओर तीव्र वेग से उतरने लगे। पाताल के अंधकार, जललोक, नागलोक, महातल — हर लोक से आगे जाते हुए भी उनके सामने वह ज्योति-स्तंभ कभी समाप्त होता न दिखा। विष्णु जितना नीचे जाते, ज्योति उतनी ही और अधिक अनंत में विलीन होती चली जाती। अंततः विष्णु समझ गए कि शिव की अग्नि-ज्योति वह नहीं जिसे मापा जा सके। वे सत्य स्वीकारते हुए शिव के पास लौट आए।

उधर ब्रह्मा ऊपर उड़ते गए — तारों के पार, ध्रुवों के पार, आकाशगंगाओं के पार। पर ज्योति का छोर इतना दूर था कि कोई अंत आता ही नहीं था। बहुत समय बीत जाने पर ब्रह्मा को अहंकार ने घेर लिया। तभी उन्हें केतकी पुष्प दिखा, जो स्वर्गीय सुगंध से भरा था। ब्रह्मा ने उससे कहा — "तुम साक्ष्य दो कि मैं ज्योति के अंतिम बिंदु तक पहुँच गया।" पुष्प मान गया। ब्रह्मा लौटे और बोले — "हे शिव, मैं पहुँच गया। यह पुष्प प्रमाण है।"

शिव की आँखें स्थिर हो गईं। उनका मुख शांत था, पर ऊर्जा प्रचंड थी। शिव बोले — "हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा। यह पुष्प भी असत्य का भागी बना है। इसलिए आज से तुम पूजा में ग्रहण नहीं किए जाओगे और यह केतकी पुष्प भी कभी मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगा।"

विष्णु का सत्य स्वीकारना और ब्रह्मा का असत्य कहना दोनों ही उस दिन ब्रह्मांड के लिए एक शिक्षा बन गए। शिव की अग्नि-ज्योति फिर शांत हो गई और उसी दिव्य ज्योति का स्थिर रूप "लिंग" कहलाया — यानी चिह्न। वह चिह्न किसी आकार का नहीं, किसी दिशा का नहीं — वह अनंत का प्रतीक है। शिवलिंग वही अनंत तेजोमय स्तंभ है, जो ब्रह्मांड के जन्म तक फैला हुआ है और प्रलय के बाद भी अपनी चेतना में स्थिर रहता है।

शिवलिंग न कोई पत्थर है, न कोई मूर्ति; वह उन आदितत्वों का संकेत है जो स्वयं ब्रह्मांड को चलाते हैं — ऊर्जा, प्रकाश, चेतना और अनंत। वही शिव का निराकार रूप है, वही सृष्टि का मूल है, वही ब्रह्म का प्रत्यक्ष चिन्ह है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवाओं को उचित मौके एवं रोजगार के अवसर देकर उनकी असीम शक्ति को विकसित गुजरात के निर्माण में जोड़ने की सिफारिशें

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट

-: छठी रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें :-

- भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुनिश्चित समयसीमा
- संयुक्त भर्ती तथा कॉमन सेंट्रल टेस्ट (सीईटी)
- हर दो वर्ष में निश्चित रिक्विजिशन विंडो
- संपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन
- कैंडिडेट फ्रेंड्ली-एंड टु एंड डैशबोर्ड
- रिक्विजिशन से नियुक्ति तक संपूर्ण डिजिटल वर्कफ्लो
- भर्ती एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि-पुनर्गठन
- कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का व्यापक उपयोग
- 10 वर्ष का भर्ती कैलेंडर

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवाओं को उचित मौके तथा रोजगार के अवसर देकर उनकी असीम शक्ति को विकसित राष्ट्र-विकसित राज्य के निर्माण में जोड़ने के दिए गए विचार को राज्य में साकार करने का दृष्टिकोण अपनाया है। श्री पटेल ने इस उद्देश्य से राज्य सरकार के प्रशासनिक ढाँचे तथा कार्य पद्धति में आवश्यक फेरबदल के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन किया है।

इस प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को अपनी छठी सिफारिश रिपोर्ट सौंपी। जीएआरसी इससे पहले तक राज्य सरकार को पाँच रिपोर्ट सौंप चुका है।

मुख्यमंत्री को बुधवार को सौंपी गई जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में राज्य में भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी, टेक्नोलॉजी से युक्त तथा युवा केन्द्रित बनाने की लगभग 9 सिफारिशें की गई हैं।

जीएआरसी की इस छठी रिपोर्ट में जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, उनके अनुसार

1. भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए निश्चित टाइमलाइन

जिस भर्ती प्रक्रिया में तीन स्टेज हों, वह 9 से 12 महीने में और जिसमें दो स्टेज हों, वह 6 से 9 महीने में पूरी करने और भविष्य में इस समयावधि से भी कम समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो; ऐसी सिफारिश की गई है।

2. संयुक्त भर्ती तथा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी)

रिपोर्ट में समान शैक्षणिक योग्यता वाले विभिन्न कैडरों के लिए संयुक्त प्रिलिम्स तथा विषयवार मेन्स परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाने की सिफारिश की गई है। इससे समान प्रकार के कैडर के लिए अलग-अलग परीक्षा पर होने वाले प्रशासनिक एवं वित्तीय खर्च में काफी कमी लाकर भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सकेगी।

3. हर दो वर्ष में दो निश्चित रिक्विजिशन विंडो

हर दो वर्ष में दो निश्चित रिक्विजिशन विंडो निर्धारित कर सभी विभागों द्वारा ऑनलाइन मांगपत्र सबमिट करने की व्यवस्था के साथ भर्ती नियमों, परीक्षा नियमों और प्रशिक्षण नियमों के लिए एक केन्द्रीय सेल का गठन करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके फलस्वरूप; भर्ती प्रक्रिया के लिए आवश्यक नियमों को बहुत तेजी से अंतिम रूप दिया जा सकेगा और भर्ती प्रक्रिया तेज बनेगी।

4. संपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन (आईएएसएस)

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हाल में होने वाली मैनुअल जाँच के स्थान पर संपूर्ण डिजिटल दस्तावेज से जाँच करने से तथा डिजी-लॉकर की तरह ही एपीआई-लिंक्ड डेटाबेस और यूनिक उम्मीदवार डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के गठन से भर्ती करने वाली संस्था और सरकारी विभागों के बीच उम्मीदवारों के दस्तावेज आसानी से भेजे जा सकेंगे और डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन भी बहुत प्रभावशाली बनेगा।

5. कैंडिडेट फ्रेंड्ली-एंड टु एंड डैशबोर्ड

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उम्मीदवार आधारित यूनिक आईडी पर एंड टु एंड डैशबोर्ड बनाया जाए, जिसमें आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की समग्र प्रक्रिया को ट्रैक किए जाने सकने की व्यवस्था के साथ जिलेवार पोस्टिंग के लिए डिजिटल माध्यम से जिला चयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

6. रिक्विजिशन से नियुक्ति तक संपूर्ण डिजिटल वर्कफ्लो

एकीकृत डिजिटल पोर्टल द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स (विभागों-एजेंसियों-उम्मीदवारों) के बीच सूचना का आदान-प्रदान संभव होगा और उम्मीदवारों को एक ही प्रकार के दस्तावेज बार-बार अलग-अलग भर्ती संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण के साथ एकरूपता की सिफारिश की गई है।

7. भर्ती एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि तथा पुनर्गठन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती के लिए नए मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (एमएसआरबी) का गठन करने और जीएसएसएसबी, जीपीएसएसबी तथा जीपीआरबी को गुजरात लोक सेवा आयोग के समक्ष आवश्यक व आर्थिक स्वायत्तता देने की सिफारिश इस रिपोर्ट में हुई है।

8. कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का व्यापक उपयोग

राज्य में जहाँ तक संभव हो, परीक्षाएँ कम्प्यूटर आधारित (कम्प्यूटर बेस्ड) ली जाएँ और ऐसी परीक्षा की प्रभावी देखरेख के लिए हर भर्ती एजेंसी में एक अलग एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट (ईएमयू) की स्थापना की जाए। यह भी सुझाव रिपोर्ट में दिया गया है।

9. 10 वर्ष का भर्ती कैलेंडर

हर विभाग के लिए भावी आवश्यकताओं पर आधारित 10 वर्ष के भर्ती कैलेंडर की समीक्षा कर बहुत ही महत्वपूर्ण इमर्जेंसी सर्विस तथा क्रिटिकल कैडर की पहचान कर हर संभव तेजी से भर्ती करने की सिफारिश जीएआरसी ने की है। देश के विकास में अग्रसर गुजरात के युवाओं को तेजी से अधिक एवं प्रभावी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प को इन सिफारिशों से पूरा किया जा सकेगा।

इतना ही नहीं; जीएआरसी द्वारा की गई ये सिफारिशें लागू करने से भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से कम समयसीमा में पूर्ण हो सके, राज्य के युवाओं को समय पर तथा पारदर्शी रोजगार के अवसर प्राप्त हों, लंबे समय से लंबित रिक्तियाँ तेजी से भरी जाएँ और सरकार की प्रशासनिक क्षमता एवं सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में गति आए; ऐसा राज्य सरकार का दृष्टिकोण साकार होगा।

मुख्यमंत्री को जीएआरसी की यह छठी रिपोर्ट सौंपे जाने के अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, प्रशासनिक सुधार प्रभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और जीएआरसी के अधिकारी उपस्थित रहे।

जीएआरसी की छठी रिपोर्ट की सिफारिशें जीएआरसी की वेबसाइट https://garcguj.in/resources पर अपलोड की गई हैं।

छापरा फूड पार्क के लॉन्च के साथ गुजरात ने कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाया

- वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) – राजकोट तथा कच्छ द्वारा मुख्य निवेशों की पूर्व समीक्षा : जीआईडीसी ने राजकोट फूड पार्क प्लान का अनावरण किया
- सौराष्ट्र का नया लॉजिस्टिक्स पावरहाउस : छापरा में जीआईडीसी पार्क का अनावरण

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात में औद्योगिक विकास की नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा राजकोट के छापरा गाँव में स्थापित होने वाले नए एग्रो फूड पार्क का अनावरण होने से सौराष्ट्र के कृषि उद्योग क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। यह पहल राज्य के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने तथा उल्लेखनीय निवेश आकर्षित करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक रणनीतिक कदम है। इस फूड पार्क द्वारा जीआईडीसी की औद्योगिक बस्तियों में उद्योगों की व्यवस्थित स्थापना तथा संगठन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सड़क, बिजली, पानी, भंडारण, प्रशिक्षण केन्द्रों, कल्वर्ट, ओवरब्रिज जैसी ढाँचागत सुविधाओं तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उद्योग क्षेत्र का सुदृढ़ संगम साकार होने वाला है।

गुजरात आज देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अग्रणियों में स्थान रखता है। केला, आलू, बाजरा तथा भिंडी जैसी फसलों के कुल 20 कृषि क्लस्टर्स के साथ राज्य में कृषि उत्पादन की विशाल क्षमता है। जामनगर, द्वारका तथा पोरबंदर जैसे जिलों में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पहले से ही मजबूत उपस्थिति है। राजकोट तो फूड प्रोसेसिंग तथा उससे जुड़े उद्योगों के लिए जाना-माना केन्द्र है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बालाजी वेफर्स ने गुजरात के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में छापरा की नई औद्योगिक बस्ती इस समग्र इकोसिस्टम को और गति देगी।

प्रोजेक्ट की झाँकी तथा स्थान के लाभ

छापरा में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले फूड पार्क को सौराष्ट्र के नए लॉजिस्टिक्स पावरहाउस के रूप में देखा जा रहा है। उसकी भौगोलिक स्थिति उद्योग क्षेत्र के लिए अनेक सुविधाओं के साथ वरदान स्वरूप है। राज्य राजमार्ग के निकट होने के कारण आंतरिक परिवहन सरल रहता है, जबकि राजकोट रेलवे स्टेशन तथा हीरापर हवाई अड्डे की निकटता उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी उलब्ध कराती है। इस फूड पार्क का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के निकट होना संचालन को अधिक तेज व कार्यक्षम बनाता है। कंडला जैसे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण निर्यात आधारित उद्योगों के लिए भी इस पार्क के एक रणनीतिक स्थान बनने की संभावना है।

निवेश की संभावनाएँ

मुख्य ढाँचागत सुविधाएँ

जीआईडीसी द्वारा पार्क में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें सुव्यवस्थित आंतरिक सड़क व्यवस्था, पेयजल, निरंतर विद्युत आपूर्ति तथा गैस पाइपलाइन जैसी मूलभूत सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अलावा; एडमिन कॉम्प्लेक्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी), स्ट्रीट लाइटिंग जैसी व्यवस्थाएँ पार्क को हर जरूरत को पूरा करेंगी। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण हमेशा प्रमुख फैक्टर होता है। इसके अनुरूप यहाँ वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ उत्पादन, रखरखाव तथा आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कार्यक्षम बनाएंगी।

गुजरात सरकार ने निवेश आकर्षित करने, टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने तथा आजीविका आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। मुद्रेथा (बनासकाँठा) और छापरा (राजकोट) स्थित प्रोजेक्ट्स इस रणनीति का मुख्य हिस्सा हैं और सामूहिक रूप से 500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य है। इस निवेश से लगभग 30,000 प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। 8 व 9 जनवरी, 2026 को राजकोट में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय परिषद् (वीजीआरसी) समग्र खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने तथा कच्छ एवं राजकोट जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सहयोगी इकोसिस्टम स्थापित करने के एक गतिशील प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा देगी।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और भुज के बीच चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा के लिए तथा अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस – भुज स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर पूर्ण आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09037/09038 बांद्रा टर्मिनस – भुज सुपरफास्ट (द्विसाप्ताहिक) स्पेशल [24 फेरे]

ट्रेन संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस – भुज सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 14:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05:50 बजे भुज पहुंचेगी। यह ट्रेन 06 दिसम्बर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09038 भुज – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को भुज से 17:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 07 दिसम्बर, 2025 से 16 जनवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, ध्रांगध्रा, सामाख्याली, भचाऊ तथा गांधीधाम स्टेशनों पर ठहरेगी।

यह ट्रेन पूर्णतः आरक्षित रहेगी तथा इस ट्रेन में एसी 3-टियर कोचेस रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09037 एवं 09038 की बुकिंग 04 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में रेल अवसंरचना को नई रफ़्तार: अंबिकापुर क्षेत्र के लिए कई नई रेल लाइन परियोजनाएँ तेज़

(जीएनएस)। अंबिकापुर तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में रेल परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति प्रदान की जा रही है। यह जानकारी आज लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दी। मंत्री ने बताया कि यह प्रश्न सांसद श्री चिन्तामणि महाराज द्वारा पूछा गया था। अंबिकापुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। बोरिडांड–अंबिकापुर (सुरजपुर) दोहरीकरण परियोजना (80 किमी) पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। अंबिकापुर–रामानुजगंज–बरवाडीह नई रेल लाइन तथा रामानुजगंज–गढ़वा रोड सहायक लाइन (262 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसी प्रकार सरडेगा–पत्थलगांव–अंबिकापुर नई रेल लाइन (218 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ के लिए रेल बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009–14 के दौरान जहाँ औसत वार्षिक आवंटन 311 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2025–26 में यह बढ़कर 6,925 करोड़ रुपये हो गया है—जो 22 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है।

नया रेल लाइनों का कमीशनिंग भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। वर्ष 2009–14 के दौरान केवल 32 किमी (औसत 6.4 किमी/वर्ष) रेल लाइनें कमीशन की गई थीं, जबकि वर्ष 2014–25 के दौरान 1,189 किमी (औसत 108.1 किमी/वर्ष) रेल लाइनें कमीशन की गईं—जो 15 गुना से अधिक वृद्धि है।

01 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित कुल 26 रेल परियोजनाएँ (06 नई लाइनें और 20 दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ) 1,931 किमी लंबाई एवं 31,619 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1,023 किमी लंबाई का कमीशनिंग पूर्ण किया जा चुका है तथा मार्च 2025 तक 16,325 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अंबिकापुर क्षेत्र सहित पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष (2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में कुल 26 सर्वेक्षणों को, कुल 3,901 किमी लंबाई को कवर करते हुए, स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति यातायात पूर्वानुमान, लाभप्रदता, पहली–अंतिम मील कनेक्टिविटी, अपूर्ण कड़ियों को जोड़ना, मार्ग विस्तार, राज्य सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों की माँगें, रेलवे की परिचालन आवश्यकताएँ तथा सामाजिक–आर्थिक महत्व जैसे मानदंडों पर आधारित होती है।

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने का समय भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, सांविधिक अनुमतियाँ, स्थानीय स्थलाकृति, कानून-व्यवस्था तथा मौसम आधारित कार्य-दिवस जैसे कारकों से प्रभावित होता है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि अंबिकापुर क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है एवं इनके त्वरित कार्यान्वयन हेतु निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी 17 नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान और सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। यह कदम राज्य सरकार की तरफ से उन विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने की कोशिश के तहत उठाया गया है, जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं।

सरकार ने कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची तैयार कर उसे सीधे शासन को सौंपें। इसके अलावा प्रदेश के सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश भी जारी किया गया है, ताकि अवैध घुसपैठियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत रखा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

योगी सरकार के इस निर्देश के बाद नगर निकायों और शासन के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। विभिन्न जिलों में रोहिंग्या घुसपैठियों का चिन्हांकन शुरू हो गया है, और प्रशासन ने उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए व्यापक सर्वे और अभियान प्रारंभ कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि चिन्हांकन अभियान में स्थानीय पुलिस, नगर निगम और राज्य प्रशासन के संयुक्त दल शामिल हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र में जांच कर अवैध प्रवासियों की पहचान करेंगे।

राज्य सरकार का यह कदम पिछले कुछ समय से रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और उनके अवैध ठहराव की चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि डिटेंशन सेंटरों के निर्माण के बाद अवैध घुसपैठियों को कानूनी कार्रवाई और निगरानी के तहत रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास को गति देने वाले हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के उपक्रम में गांधीनगर में चौथी समीक्षा बैठक आयोजित की

- 11,360 करोड़ रुपए के कुल 27 प्रोजेक्ट्स के कामकाज की समीक्षा की गई
- प्रोजेक्ट्स उनकी निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों तथा गुणवत्ता में कोई कम्प्रोमाइज न हो; यह सुनिश्चित करने का मुख्यमंत्री का सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश

-: मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षित प्रोजेक्ट्स :-

- रेलवे के 6 प्रोजेक्ट्स - 4190.96 करोड़ रुपए
- उद्योग एवं खान विभाग से जुड़े 6 प्रोजेक्ट्स – 3657.62 करोड़ रुपए
- शहरी विकास विभाग के 12 प्रोजेक्ट्स – 3511.91 करोड़ रुपए

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास को अधिक गति देने वाले 146 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के कामकाज की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक करने का नूतन दृष्टिकोण अपनाया है।

श्री पटेल ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को गांधीनगर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कुल 11,360 करोड़ रुपए के कुल 27 प्रोजेक्ट्स के कामकाज की समीक्षा की। इन प्रोजेक्ट्स अंतर्गत रेलवे से जुड़े 4, उद्योग एवं खान विभाग से जुड़े 6 और शहरी विकास विभाग के 15 प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन तथा समीक्षा हुई। उन्होंने राज्य के ऐसे हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की सर्वग्राही समीक्षा के उपक्रमों में अब तक तीन समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में लगभग 67 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के दौरान उनके दिए गए सुझावों के संदर्भ में सम्बद्ध विभागों द्वारा किए गए कामकाज पर भी इस चौथी समीक्षा बैठक में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत@2047 के विजन से सुसंगत विकसित गुजरात के लिए ये सभी विकासोन्मुखी हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पथदर्शक हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोजेक्ट्स उनकी निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों तथा गुणवत्ता में कोई कम्प्रोमाइज न हो; यह सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश बैठक में दिए।

इतना ही नहीं; उन्होंने बैठक में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा कि वे रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में जमीन से सम्बद्ध मामलों के त्वरित निवारण के लिए सम्बद्ध जिला कलेक्टरों को निर्देश दें।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिन 27 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की सघन समीक्षा की; उनमें रेलवे से जुड़े 4190 करोड़ रुपए के छह प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत सामखियाळी-गांधीधाम रेलवे के चार मार्गीकरण, राजकोट-कानालुस 122 किलोमीटर लाइन की डबलिंग, नलिया तथा वयोर के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन, मोटी आदरज-वीजापुर गेज कन्वर्जन, वीजापुर-आंबलियासण गेज कन्वर्जन और नलिया-जखौ नई लाइन के प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य में समग्रतया रेलवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की।

इसके अतिरिक्त; उन्होंने उद्योग एवं खान विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट अंतर्गत धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट फेज-1 का डेवलपमेंट, नवसारी के पीएम मित्र पार्क में 65 एमएलडी जलापूर्ति योजना, बल्क ड्रग पार्क डेवलपमेंट, मोरबी के रफाळेश्वर के गति शक्ति कारगो टर्मिनल का निर्माण और भरूच के सायखा में 90 एमएलडी की डीप सी इफ्लुएंट डिस्पॉजिल पाइपलाइन आदि के 3657.62 करोड़ रुपए मूल्य के 6 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डीप सी इफ्लुएंट डिस्पॉजल पाइपलाइन के कार्यों को समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया।

धोलेरा एसआई के सीईओ श्री कुलदीप आर्य ने जानकारी दी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अधिकांश कार्य पूर्ण हो गया है और जेटको द्वारा 66 केवी सब स्टेशन के लिए तथा सिंचाई विभाग द्वारा उनके वर्कऑर्डर दे दिए हैं।

शहरी विकास विभाग से जुड़े 15 प्रोजेक्ट्स अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन में अहमदाबाद में 14 मेगावाट के वेस्ट टु एनर्जी प्लांट, खारीकट कैनाल डेवलपमेंट के 1 से 5 फेज, गांधी आश्रम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तथा वाडज में पीपीपी आधारित झोंपड़पट्टी पुनर्वास प्रोजेक्ट की भी बैठक में समीक्षा की गई।

इसके अलावा; जामनगर-लालपुर बाईपास जंक्शन पर फोर लेन फ्लाईओवर, सूरत महानगर में बीआरटी क्रॉसिंग पर फोर लेन फ्लाई ओवरब्रिज की प्रगति की जानकारी बैठक में दी गई।

शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन ने जूनागढ शहर के अंडर ग्राउंड ड्रैनेज प्रोजेक्ट के कामकाज का भी विवरण दिया।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, सम्बद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव, रेलवे के डीआरएम, वरिष्ठ सचिव, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह तथा मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहभागी हुए।

कैलिफ़ोर्निया में बुकी राकेश राजदेव के घर गोलियों की बारिश, अंतरराष्ट्रीय अपराध जगत में मचा भूचाल-रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी

(जीएनएस)। अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया जैसे शांत और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका धागा भारत के अंडरवर्ल्ड और अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़ जाएगा। बुधवार देर रात कैलिफ़ोर्निया स्थित गुजरात के बुकी और कारोबारी राकेश राजदेव के आलीशान घर पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की दूरी, आवाज और धमाके आसपास के घरों तक सुनाई दिए। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े एक अकाउंट ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नया भूचाल खड़ा कर दिया। 'नवीन बॉक्सर' नाम के फेसबुक प्रोफाइल से स्टेटस पोस्ट हुआ—और पोस्ट में दावा किया गया कि यह हमला रोहित गोदारा गैंग ने किया है। पोस्ट में लिखा गया कि राकेश राजदेव को जिस तरह दुबई में 'झटका' दिया गया था, कैलिफ़ोर्निया में यह फायरिंग उसी का अगला कदम है। धमकी में यह भी कहा गया कि चाहे 40 गार्ड हों या 400, "हमारे लिए किसी भी देश में मरवाना मुश्किल नहीं है।"

पोस्ट में दो कुख्यात नाम—महेंद्र डेलाना और राहुल रिनाउ—का जिक्र हुआ और कहा गया कि उनके इशारे पर ही राकेश के घर गोलियां चलाई गईं। इतनी सार्वजनिक जिम्मेदारी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय गैंगवार का रूप लेने लगा है।

गुजरात का यह बुकी लंबे समय से भारत की जांच एजेंसियों के रडार पर है। 2022 और 2023 में बेटिंग ऐप और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामलों में पुलिस ने उस पर FIR दर्ज की। इसके बाद 2023 में ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खोला और कई ठिकानों पर छापेमारी की। लेकिन कार्रवाई शुरू होने

से पहले ही राकेश देश छोड़कर फरार हो गया। तब से वह दुबई, श्रीलंका और अमेरिका के अलग-अलग स्थानों पर देखे जाने की खबरें आती रहीं।

कहा जाता है कि राकेश, मोस्ट वांटेड अपराधी सौरभ महादेव का बेहद करीबी है और दोनों मिलकर अवैध सट्टेबाजी का करोड़ों का नेटवर्क चलाते रहे हैं। अब इस फायरिंग के बाद दोनों का दायरा एक और खतरे में घिरता दिख रहा है।

रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्ट के अनुसार राकेश राजदेव और महादेव बुक ऐप के संचालक सौरभ महादेव पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं। यहां तक लिखा गया कि सौरभ दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई से मिलने जा चुका है। गैंग ने चेतावनी देते हुए कहा, "जो पाकिस्तान को फंडिंग करेगा, वह हमारा दुश्मन होगा। अपने देश की मिट्टी के नहीं हुए, तो किसी के भी नहीं हो सकते।"

इस तरह का बयान गैंगस्टर दुनिया में युद्ध की घोषणा जैसा माना जा रहा है—जहां अब अवैध कारोबार, पैसों का नेटवर्क और आपसी टकराव नए खतरनाक मोड़ ले रहे हैं। पोस्ट के अंत में जिन नामों का जिक्र है—रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, काला जठेड़ी, नरेश सेठी, काला राणा, लिप्पन नेहरा—ये उत्तर भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स माने जाते हैं। यह सभी अब लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के तहत एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जो पहले ही कई हाई-प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार है।

अब तक अमेरिकी पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कैलिफ़ोर्निया पुलिस का कहना है कि घटना की जांच गंभीरता से की जा रही है क्योंकि यह मामला केवल स्थानीय अपराध का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का दिख रहा है।

भारत की एजेंसियां भी सतर्क हैं, क्योंकि महादेव बुक ऐप पहले से ही एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है, और अब अपराधियों के बीच खुला गैंगवार इसका दायरा और बढ़ा रहा है।

कैलिफ़ोर्निया में हुई यह फायरिंग सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि उस वैश्विक अपराध नेटवर्क की झलक है, जो भारत से लेकर दुबई और अब अमेरिका तक फैल चुका है।

जहां कानून, व्यवसाय और अंडरवर्ल्ड तीनों एक-दूसरे में उलझते जा रहे हैं—और हर गोली के पीछे करोड़ों की राजनीति, खुफिया कड़ियां और साजिशें छिपी हैं।

दुनियाभर की एजेंसियों के लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आने वाली बड़ी गैंगवार का संकेत भी हो सकती है।

खेड़ा में तेंदुए का कहर: उधमतपुरा गांव में चीख-पुकार, तीन लोग लहूलुहान, पूरी रात दहशत में गुज़रा इलाका

(जीएनएस)। गुजरात के खेड़ा ज़िले का उधमतपुरा गांव बुधवार की सुबह एक सामान्य दिन की तरह ही जागा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरे गांव का माहौल चीख-पुकार, भागदौड़ और डर से भर गया। खेतों और मकानों के बीच से अचानक निकलकर आए एक तेंदुए ने पूरे गांव को पंगु कर दिया। लोगों के हाथ-पैर फूल गए, किसी को समझ नहीं आया कि कहां भागना है और कैसे बचना है। यह घटना केवल एक हमले की नहीं, बल्कि उस गहरे खतरे की तस्वीर है, जिससे ग्रामीण कई महीनों से जूझ रहे हैं—मानव और वन्यजीव के बीच बढ़ता संघर्ष।

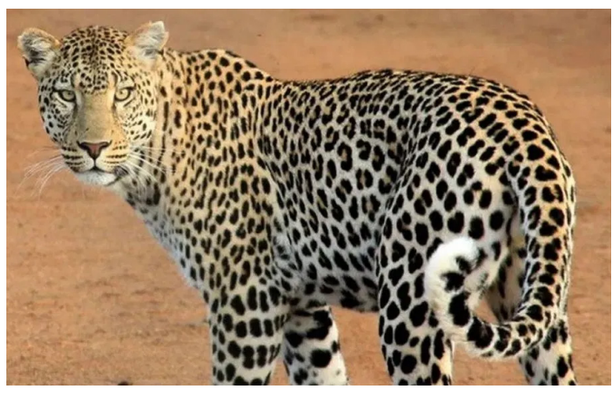

उधमतपुरा में रहने वाला एक युवक सुबह रोज़ की तरह काम पर निकल रहा था, तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक विशाल तेंदुआ उस पर टूट पड़ा। युवक के चिल्लाने की आवाज़ ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। लोग घरों से बाहर भागे, किसी ने बच्चे को गोद में उठाया, किसी ने दरवाज़े बंद किए, और कुछ बहादुर लोगों ने दूर से पत्थर फेंककर तेंदुए को भगाने की कोशिश की। लेकिन तेंदुआ एक-दो हमलों के बाद रुका नहीं। भगदड़ में उसने दो और ग्रामीणों पर भी झपट्टा मार दिया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके कपड़े व शरीर पर गहरे पंजों के निशान साफ दिखाई दिए।

जो वीडियो सामने आया है, उसमें गांव की गलियों में लोगों की चीखें, दौड़ते कदम, और बीच-बीच में तेंदुए की झलक पूरे मामले की भयावहता को बयान करती है। गांव का हर शख्स इस बात से सहमा हुआ है कि यह सब कुछ कुछ ही मिनटों में हो गया और कोई भी इसे रोक नहीं सका।

तत्काल ग्रामीणों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें गहन चिकित्सा में रखा गया है। तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मानसिक तनाव पूरे गांव में साफ महसूस किया जा सकता है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, महिलाएँ खेतों में अकेले जाने से कतराने लगी हैं और बुज़ुर्ग यह कहते नहीं थक रहे कि ऐसा आतंक उन्होंने दशकों में पहली बार देखा है।

वन विभाग की टीम सूचना मिलते ही गांव पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। टीम ने पूरे इलाके में पिंजरे लगाए, गांव के चारों ओर गश्त बढ़ा दी और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वन अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में जंगल की ओर लगातार बढ़ती मानवीय गतिविधि और कम होती प्राकृतिक शिकार की उपलब्धता के कारण तेंदुए गांवों की ओर भटक रहे हैं।

उधमतपुरा और उसके आसपास के गांवों के लोग अब दिन-रात इस बात की चिंता में जी रहे हैं कि अगला हमला कब और किस पर हो सकता है। गांव की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं, बल्कि आशंकाओं से भर गई हैं। लोग अपनी नींद खो चुके हैं, बच्चों को घरों से बाहर खेलने नहीं दिया जा रहा, और खेतों का काम भी तनातनी के साथ किया जा रहा है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तेजी से बदलते पर्यावरण और मानवीय विस्तार के बीच आखिर कब तक ग्रामीण ऐसे खतरों का सामना करते रहेंगे। फिलहाल गांव वालों की एक ही मांग है—तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके डर के साए को खत्म किया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो सके।

हैदराबाद में ऑटो से मिली दो लाशें—सुई, सिरिंज और ड्रग्स के ओवरडोज़ का शक शहर को दहला देने वाली घटना ने बढ़ाई चिंता

(जीएनएस)। हैदराबाद की एक सामान्य सुबह अचानक खौफ में बदल गई, जब चंद्रयानगुट्टा के व्यस्त इलाके में रुमान रेस्टोरेंट के ठीक सामने खड़े एक ऑटो से दो युवकों के शव बरामद हुए। इस इलाके में रोज़ाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं, दुकानों की आवाजाही रहती है, और सड़क पर हलचल हमेशा बनी रहती है। लेकिन उस सुबह यह हलचल अचानक ठहर गई, जब लोगों ने एक ऑटो को घंटों से एक ही जगह खड़ा देखा और अंदर दो लोगों को निर्जीव हालत में पड़ा पाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही जांच शुरू हुई, ऑटो के अंदर रखी चीज़ों ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। सीट के नीचे पड़ी सुई, खाली सिरिंज और वह गंध, जिसने तुरंत इस ओर इशारा कर दिया कि कहानी सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि उस नशे की है जो धीरे-धीरे हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की नसों में जहर की तरह फैल रहा है।

पुलिस ने शवों की पहचान इरफान और जहांगीर के नाम से की, जो दोनों पास के ही इलाके में रहते थे। दोनों की उम्र ऐसी थी जहां आम तौर पर लोग अपने सपनों की डगर पर निकलते हैं, लेकिन इन्हें शायद नशे की गिरफ्त ने उन सपनों तक पहुंचने ही नहीं दिया। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि दोनों की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। ऑटो के भीतर पड़ा हर सबूत इस आशंका को और पुख्ता कर रहा था। दोनों के शरीर ढीले पड़े थे, आंखें आधी खुली, और हाथों में नशे का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उन्हें उस्मानिया अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमॉर्टम से मौत की सटीक वजह सामने आएगी, पर माहौल में जो फुसफुसाहट थी वह यही कह रही थी कि नशा फिर दो जिंदगियां ले चुका है।

यह घटना इसलिए और डरावनी लगती है क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ ही सप्ताह पहले बेगमपेट के इंपीरियल हाउस अपार्टमेंट के सामने एक महिला लिसा को भी संदिग्ध हालत में पाया गया था। उस महिला के शरीर पर चोटों के निशान थे और उसके बारे में भी शुरूआती शक नशे की लत की तरफ ही गया था। पुलिस ने उस मामले की जांच की, पर इतने दिनों बाद फिर शहर का एक कोना ऐसी ही घटना का गवाह बना, जिससे साफ होता है कि हैदराबाद की सड़कों पर नशे के नेटवर्क ने गहरी पकड़ बना ली है। पुलिस अधिकारी मानते हैं कि यह लगातार बढ़ती हुई लत और सप्लाई चेन का संकेत है, जिससे निपटना अब बेहद जरूरी हो गया है। इरफान और जहांगीर की मौत ने इलाके के लोगों को झकझोर दिया है। दिनभर दुकानदार, राहगीर और स्थानीय निवासी इसी चर्चा में लगे रहे कि आखिर यह ड्रग्स शहर में कहां से आ रहा है, कौन लोग इसे फैला रहे हैं, और क्यों नौजवान इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं।

भावनगर के हेल्थ कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, धुएं से भरा पूरा परिसर; खिड़कियां तोड़कर निकाले गए मरीज, 50 दमकलकर्मी रात–दिन जुटे

(जीएनएस)। गुजरात के भावनगर में बुधवार सुबह का समय हमेशा की तरह शांत था, लेकिन कुछ ही मिनटों में कालूभा रोड स्थित एक बड़े कॉम्प्लेक्स ने आग और अफरातफरी का वह मंजर देखा, जिसे याद कर आज भी लोग सिहर उठे। यह कॉम्प्लेक्स कई अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर्स, ऑफिसों और दुकानों से घिरा हुआ है—इसलिए जैसे ही धुआं पहली बार बाहर निकलता देखा गया, पूरा परिसर दहशत और भागदौड़ से भर उठा।

शुरुआत एक पैथोलॉजी लैब से हुई, जहां अचानक तेज़ लपटें उठीं। कुछ ही मिनटों में आग ने लैब के आसपास स्थित दुकानों, केबिन, क्लिनिक और यहां तक कि अस्पतालों के हिस्सों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों का अस्पताल भी था, जहां धुआं भरते ही मासूमों की सांसें उखड़ने लगीं। डॉक्टरों और नर्सों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन डर के बावजूद सभी ने मिलकर मरीजों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष किया।

अस्पताल के कमरों, वार्डों और गलियारों में घुटन बढ़ने लगी थी। कई बुजुर्ग मरीज व्हीलचेयर पर थे, कुछ बच्चों के चेहरे पूरी तरह धुएं से काले पड़ गए थे। कुछ मरीज तो घबराहट में बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। यही वजह थी कि फायर ब्रिगेड को खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। बाहरी सीढ़ियों और टूटे कांच के रास्ते एक–एक मरीज, एक–एक बच्चा सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई छोटे बच्चों को शीशा तोड़कर हाथों और स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया।

फायर ऑफिसर प्रद्युम्न सिंह जडेजा के अनुसार, अब तक 19–20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका था। बचाव टीमों ने कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई होती, तो स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी।

जैसे ही आग की तस्वीरें और जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचीं, शहर के अलग–अलग हिस्सों से दमकल वाहन मौके पर दौड़ पड़े। देखते ही देखते 10 दमकल गाड़ियां एक साथ पहुंच गईं। करीब 50 फायर फाइटर्स ने बिना देर किए पानी की बौछारें शुरू कर दीं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ मिनटों में ही काले धुएं ने पूरी इमारत को घेर लिया। दमकलकर्मी लगातार मास्क बदलते रहे, क्योंकि अंदर का धुआं बेहद जहरीला हो चुका था।

कॉम्प्लेक्स के पास रहने वाले लोगों ने भी बिना वक्त गंवाए बचाव कार्य में हाथ बंटाया। किसी ने पानी की बोतलें मरीजों को दीं, किसी ने स्ट्रेचर उठाया, तो किसी ने फायर कर्मियों को रास्ता साफ करने में मदद की। महिलाओं ने बच्चों को संभाला, पुरुषों ने घायलों को बाहर लाने में फायर टीम की सहायता की।

फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन कूलिंग का काम अभी जारी है ताकि किसी भी हिस्से में दोबारा चिंगारी न उठ सके। आग के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है—शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक बयान जांच के बाद ही आएगा। लोगों से अपील की गई है कि कॉम्प्लेक्स के आसपास भीड़ न लगाएं, ताकि बचाव दल तेजी से काम कर सके।

इस पूरी घटना ने लोगों को डरा भी दिया और राहत भी दी। डर इसलिए कि आग इतनी तेजी से फैली कि किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, और राहत इसलिए कि बड़ी आफत के बावजूद अब तक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

भावनगर के लोगों के लिए यह दिन हमेशा याद रहेगा—एक ऐसा दिन जब खतरे और हिम्मत दोनों एक–दूसरे से टकराए और इंसानियत ने जीत हासिल की।

सरकार का बड़ा कदम: हर पान मसाला पैक पर अब खुदरा बिक्री मूल्य अनिवार्य

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पान मसाला उद्योग पर निगरानी और कर व्यवस्था को सख़्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) दूसरा (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित करते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि देश में बिकने वाले हर पान मसाला पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य (MRP/RSP) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। यह नियम 1 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगा।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार अब पान मसाला के किसी भी आकार या वजन के पैक को बिना आरएसपी प्रिंट किए बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होगी। 10 ग्राम या इससे छोटे पाउच पर भी मूल्य अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले नियम

26(a) के तहत छोटे पैकेटों पर कुछ घोषणाओं में छूट मिलती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

नए नियम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 में निर्धारित सभी अनिवार्य विवरण—जैसे निर्माता का नाम, निर्माण तिथि, बैच नंबर, सामग्री का वजन, और उपभोक्ता शिकायत संपर्क—हर पैक पर दर्ज हों। पान मसाला श्रेणी के लिए एक नया अनिवार्य घोषणा तत्व भी जोड़ा गया है, जिससे बाजार में बिकने वाले सभी उत्पाद एक ही मानक के तहत आएंगे।

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से सबसे बड़ा लाभ आरएसपी आधारित जीएसटी की सटीक वसूली में होगा। पान मसाला उद्योग में लंबे समय से कई पैक साइज और अनियमित मूल्य प्रिंटिंग के कारण कर संग्रह में अस्पष्टता रही है। अब हर पैक पर साफ मूल्य अंकित होने से कर निर्धारण पारदर्शी होगा, राजस्व नुकसान रुकेगा और जीएसटी काउंसिल के निर्णयों को लागू करना आसान होगा।

सरकार का यह कदम छोटे पैकेटों की आड़ में हो रही कर चोरी को रोकने, उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने और बाजार में समान अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

इंडिगो की कई उड़ानें ठप : माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तकनीकी खामी बनी वजह,दो दिन में 42 फ्लाइटें रद्द, एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड व वैकल्पिक उड़ानें देने की पेशकश की

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बुधवार की सुबह दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, गोवा और लखनऊ सहित देश के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर अचानक हलचल बढ़ गई। इंडिगो एयरलाइंस के काउंटरों पर लंबी कतारें लग चुकी थीं, अनाउंसमेंट तेज़ी से होने लगे थे और परेशान यात्रियों की भीड़ इधर-उधर समाधान तलाश रही थी। वजह थी—माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आई एक वैश्विक तकनीकी खामी, जिसने अचानक इंडिगो के पूरे ऑपरेशनल सिस्टम को प्रभावित कर दिया और उड़ान संचालन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।

तकनीकी गड़बड़ी इतनी व्यापक थी कि कई उड़ानें निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर पाईं, कई को रनवे पर ही रोक दिया गया और कई को रद्द करना पड़ा। यात्रा पर निकल चुके लोगों को अचानक संदेश मिला कि उनकी फ्लाइट देर से चलेगी, लेकिन थोड़ी देर में ही दूसरी सूचना आ गई कि उड़ान रद्द कर दी गई है। इस अनिश्चितता ने यात्रियों में गुस्सा और बेचैनी दोनों पैदा कर दिए। कई लोग बिज़नेस मीटिंग, इंटरव्यू, मेडिकल अपॉइंटमेंट और पारिवारिक समारोहों में देर होने की चिंता में

एयरलाइन काउंटरों के चक्कर लगाते रहे।

एयरलाइन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि अप्रत्याशित तकनीकी खामी के कारण सिस्टम प्रभावित हुआ है और तकनीकी टीमें इसे जल्द से जल्द ठीक करने में जुटी हैं। इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा है कि वे चाहे तो अगली उपलब्ध उड़ान ले सकते हैं या फिर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। एयरलाइन ने यह भी सलाह दी कि कोई भी यात्री एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले वेबसाइट पर अपनी उड़ान की ताज़ा स्थिति अवश्य चेक करें, क्योंकि परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं।

सबसे बड़ी परेशानी उन यात्रियों को हुई जो छोटे बच्चों, बुजुर्गों या भारी सामान के साथ सुबह-सुबह एयरपोर्ट पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी यात्रा के बिखरने की कहानियाँ साझा कीं—किसी ने बताया कि वह छह घंटे से एयरपोर्ट पर फंसा है, किसी ने कहा कि उसकी फ्लाइट तीन बार री-शेड्यूल हुई और आखिरकार रद्द हो गई, तो किसी ने गुस्से में लिखा कि एयरलाइन को ऐसे हालात में यात्रियों को बेहतर सहायता देनी चाहिए थी।

तकनीकी समस्या के चलते पिछले दो दिनों में कुल 42 उड़ानें रद्द की गई हैं। इनमें 22 आगमन और 20 प्रस्थान की उड़ानें शामिल हैं। अचानक हुए इतने बड़े पैमाने के रद्दीकरण से एयरलाइन का पूरा शेड्यूल अस्त-व्यस्त हो गया है और कई क्रू सदस्यों को भी तत्काल पुनः तैनात करना पड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार, जब किसी बड़े नेटवर्क में अचानक तकनीकी खामी पैदा होती है, तो उसका असर कई घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक दिखाई दे सकता है। हालांकि इंडिगो ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति लगातार बेहतर हो रही है और जल्द ही सामान्य संचालन बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन बुधवार को जिन यात्रियों की योजनाएँ प्रभावित हुईं, उनके लिए यह दिन लंबी प्रतीक्षा, हताशा और अनिश्चितता से भरा रहा। एयरलाइंस उद्योग में ऐसी तकनीकी गड़बड़ियाँ दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन इस बार इसका असर जिस व्यापकता से देखने को मिला, उसने यात्रियों, एयरलाइन और देश के प्रमुख हवाई अड्डों सभी को चुनौती के सामने खड़ा कर दिया।

वाराणसी में कफ सिरप तस्करी कांड पर ईडी की बड़ी कार्रवाई

मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के दो ठिकानों पर ताला, नोटिस चस्पा-जांच का दायरा और बढ़ा

(जीएनएस)। वाराणसी। नशीले कफ सिरप की तस्करी से जुड़े बहुचर्चित और अरबों की अवैध कमाई वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को वाराणसी में एक और बड़ी कार्रवाई की। मामले के मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल की चल-अचल संपत्तियों की जांच तेज करते हुए टीम शहर के दो प्रमुख ठिकानों—प्रहलादघाट स्थित पैतृक घर और सिगरा स्थित 'दुर्गा निवास'—पर पहुंची। सुबह करीब 10 बजे लखनऊ जोनल कार्यालय के सहायक निदेशक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय ईडी टीम प्रहलादघाट के कायस्थ टोला इलाके में स्थित शुभम जायसवाल के पैतृक मकान पर पहुंची। लेकिन वहां सन्नाटा पसरा था। मकान के मुख्य दरवाजे पर बड़ा ताला लटका हुआ था और कोई भी परिजन मौजूद नहीं था। टीम ने औपचारिक कार्रवाई करते हुए ताले से जड़े दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कई दिनों से घर पूरी तरह बंद

है और कोई भी अंदर-बाहर आते नहीं देखा गया।

इसके बाद टीम सिगरा स्थित दुर्गा निवास पहुंची, जिसे शुभम का दूसरा अहम ठिकाना बताया जा रहा है। यहां उसकी मां और बहन मौजूद मिलीं। ईडी टीम ने नोटिस सीधे शुभम की मां को सौंपा और उनसे भी कुछ प्राथमिक जानकारी ली। परिवार पर भी जांच एजेंसियों की कड़ी निगरानी बनी हुई है, क्योंकि करोड़ों रुपये की संपत्तियों की खरीद-बिक्री और फंड के प्रवाह में परिवार के कई सदस्यों पर भी संदेह जताया जा रहा है।

शुभम जायसवाल पर आरोप है कि वह कई राज्यों में फैले नशीले कफ सिरप के बड़े अवैध नेटवर्क का संचालन करता था, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में कोडीन आधारित कफ सिरप की तस्करी बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल सहित कई हिस्सों में होती थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस कारोबार से करोड़ों रुपये की अवैध कमाई होती थी, जिसे अलग-अलग नामों से प्रॉपर्टी, जमीन और व्यवसायों में निवेश किया जाता रहा। इसी अवैध धन को लेकर ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

मामले में एक बड़ा खुलासा तब हुआ, जब मुख्य आरोपित के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। बताया गया कि वे दुबई भागने की कोशिश में थे। पूछताछ में उन्होंने यह स्वीकार भी किया कि उनका बेटा शुभम फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है और वहीं से नेटवर्क को संचालित कर रहा है। सोनभद्र पुलिस ने भोला प्रसाद को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर एसआईटी के हवाले कर दिया है, जो लगातार गहराई से पूछताछ कर रही है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में जुट चुकी है। उसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया न्यायालय में शुरू हो चुकी है। एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और अवैध कारोबार से जुड़े कई गंभीर मामलों में वांछित शुभम की गिरफ्तारी के लिए पांच विशेष पुलिस टीमें सक्रिय हैं और उसके विदेशी ठिकानों का भी पता लगाया जा रहा है।

वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, चंदौली और गाजियाबाद के अलावा कई अन्य जिलों में शुभम पर गंभीर धाराओं में मामलों का अंबार है। ईडी की जांच आगे बढ़ने के साथ इस पूरे नेटवर्क के और भी परतें खुलने की उम्मीद है, जिससे यह सामने आएगा कि नशीले कफ सिरप की इस अवैध तस्करी में कौन-कौन शामिल था और किसने इसके जरिए अरबों रुपये की काली कमाई को वैध रूप में बदलने का प्रयास किया। जांच एजेंसियां इस मामले को देश के सबसे बड़े संगठित नशीली दवा तस्करी के rackets में से एक मान रही हैं, और आने वाले दिनों में इस पर और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

धर्मेंद्र की अस्थियों का गंगा में शांतिपूर्वक विसर्जन

सनी-बॉबी देओल ने हरिद्वार में गोपनीय रूप से पूरा कराया संस्कार, निजी घाट पर कर्मकांड होने से पुरोहित समाज नाराज़

(जीएनएस)। हरिद्वार। हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' और दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता धर्मेंद्र को उनके परिजनों ने बुधवार सुबह गंगा तट पर अंतिम विदाई दे दी। सनी देओल, बॉबी देओल और पूरे देओल परिवार ने हरिद्वार पहुंचकर अत्यंत गोपनीय ढंग से अभिनेता की अस्थियों का विसर्जन किया। भावुक माहौल में पूरा कर्मकांड शास्त्रीय विधियों के अनुसार संपन्न हुआ।

परिवार मंगलवार शाम को ही अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंच गया था। देओल परिवार का आगमन न तो होटल प्रबंधन ने सार्वजनिक किया और न ही घाट पर किसी प्रकार की भीड़ की अनुमति थी। सभी सदस्य सीधे होटल पीलीभीत में रुके, जहाँ से बुधवार तड़के अस्थि कलश को होटल के पिछले हिस्से में बने निजी घाट की ओर ले जाया गया। गंगा किनारे परिवारीजनों ने मौन साधा, पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया और फिर धर्मेंद्र की अस्थियों को गंगा की पावन धारा को समर्पित कर दिया गया।

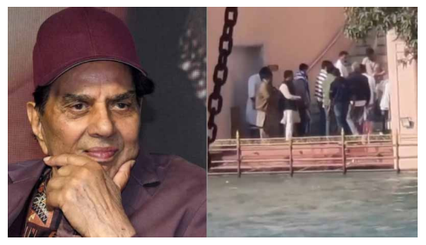

सनी और बॉबी दोनों पूरी प्रक्रिया के दौरान बेहद भावुक दिखाई दिए। घाट पर उपस्थित सीमित सदस्यों ने गंगा स्नान किया और शांतिपूर्वक वापस लौट गए। पूरा कार्यक्रम बिना किसी मीडिया या बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति के सम्पन्न हुआ। अस्थि विसर्जन के तुरंत बाद परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया।

इधर, इस गोपनीयता और निजी घाट पर किए गए विसर्जन को लेकर हरिद्वार के पुरोहित समाज ने नाराज़गी व्यक्त की है। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि हरिद्वार हिंदू समाज का प्राचीन और मान्य तीर्थ है—विशेषकर हरकी पैड़ी, जहाँ शास्त्रों के अनुसार अस्थि विसर्जन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जैसा बड़ा व्यक्तित्व जब हरिद्वार आया, तो उम्मीद थी कि संस्कार हरकी पैड़ी पर ही किया जाएगा। निजी घाट पर विसर्जन होने से परंपरा और स्थानीय पुरोहितों की भावनाओं को ठेस पहुँची है।

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया था। बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें अंतिम विदाई दी थी, और अब हरिद्वार में उनकी अस्थियों को गंगा में समर्पित करने के साथ ही उनके पार्थिव सफर का अंतिम अध्याय भी पूर्ण हुआ।

गंगा की पावन धारा में खोती अस्थियों के साथ देओल परिवार की आंखों में केवल एक ही भावना थी—पिता और महान अभिनेता धर्मेंद्र के प्रति अपार प्रेम, सम्मान और स्मृति की अनंत गूंज।